अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद् के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण

नई दिल्ली
6 नवम्बर, 2006

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद के रजत जयंती समारोह में आकर वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरे लिए एक तरह से यह घर लौटने जैसी बात है, क्योंकि मुझे इस परिषद की आम सभा का संस्थापक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं परिषद के संस्थापक और निर्माता श्री के.बी. लाल की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। वे जब तक जीवित रहे, परिषद के कार्य में पूरी दिलचस्पी लेते रहे। परिषद के शासी बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटने के बाद वे अक्सर लाइब्रेरी में आते थे और गोष्ठियों में भाग लेते थे।

श्री के.बी. लाल दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारियों की उस पीढ़ी के सही प्रतिनिधि थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शुरू के वर्षों में सौभाग्य से भारत को मिली। उन्होंने महान संस्थाओं के निर्माण और विकास में राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद की परिकल्पना 1980 के दशक के शुरू के वर्षों में की गई, जब श्रीमतीइंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमें अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर ज्यादा ध्यान देना है। आपको याद होगा कि 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सरकार ने औद्योगिक और व्यापार नीतियों के अनेक पहलुओं का फिर से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की कई समितियों का गठन किया था। जिन विशिष्ट हस्तियों ने उस समय अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उनमें से कुछ यहां मौजूद हैं और मैं विशेष रूप से डा0 विजय केलकर का नाम लेना चाहूंगा यह वह समय था, जब चीन ने **चार आधुनिकीकरण** नाम से अभियान शुरू किया था। और वह बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा खुला होता जा रहा था।

श्री के.बी. लाल इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि भारत को और अधिक अंर्तमुखी अर्थव्यवस्था न होकर ज्यादा बहिर्मुखी होना होगा। इसके लिए घरेलू नीति को तैयार करने और उसमें परिवर्तन करने की जरूरत थी। इसके लिए जरूरी था कि भारतीय फर्में और अधिक स्पर्धाशील बनें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद के संस्थापकों ने इन सभी मुद्दों का अध्ययन करने और नीति संबंधी मार्ग निर्देशन देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया। यह उचित ही था कि शुरू में इस परिषद का कार्यालय इंडिया इंटर नेशनल सेंटर के परिसर में था।

मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद के एक के बाद एक जो निष्ठावान अध्यक्ष तथा निदेशक बने, वे परिषद के संस्थापकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। इस संदर्भ में श्री आर एन मल्होत्रा के योगदान की मैं बहुत सराहना करता हूं, जिनके बाद डा. आई.जी. पटेल शासी बोर्ड के अध्यक्ष बने। डा. श्रीमती ईशर आहलूवालिया विभिन्न पदों पर रहते हुए परिषद के साथ जुडे रहीं और उन्होंने इस चिंतनशील संस्था को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रगतिशील संस्था का स्वरूप देने में योगदान दिया। परिषद ने व्यापार नीति औद्योगिक नीति, विनिमय दर और भुगतान संतुलन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली, पूंजी आगमन आव्रजन और श्रम नीतियों से संबंधित अनेक नीतियों पर

अनुसंधान कार्य किए और इन सभी क्षेत्रों में इन मुद्दों पर चल रही विचार धाराओं पर गहरा प्रभाव डाला। मेरे विचार में परिषद को इसी तरह से काम जारी रखना चाहिए और देश ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्रमुख चिंतनशील संस्था के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए।

पिछले कुछ महीनों में मैने कई बार कहा है कि मेरे विचार में भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में कोई बाहरी अड़चने नहीं हैं। ज्यादातर अड़चने अंर्तनिहीत अड़चने हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहरी गतिविधियां या प्रवृतियां हमारी विकास प्रक्रियाओं के रास्ते में कभी रूकावट नहीं बन सकतीं। न ही इसका मतलब यह है कि हमने सभी उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाया है ।इसका मतलब सिर्फ यही है कि आज विश्व का वातावरण भारत के विकास के प्रति इतना अनुकूल है, जितना पिछले वर्षों में कभी नहीं था। लेकिन हमें अपनी विकास प्रक्रिया के लिए पैदा होने वाली किसी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैश्विक प्रवृतियों का पूर्वानुमान लगाने और हमारे पर होने वाले इनके प्रभावों को समझने के लिए हमें आवश्यक विश्लेषक साधन (औजार) विकसित करने होंगे और नीति संबंधी ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी जो गतिशील हों, लेकिन हमारी आवश्यकयताओं के अनुरूप उनमें लचीलापन भी हो। अन्य बातों के अलावा इसके लिए हमें विश्व के आर्थिक परिदृश्य का लगातार अध्ययन करना है और अपनी नीतियों के प्रारूप के लिए इसे संदर्भ के रूप में समझना है। मेरे विचार से परिषद के कार्य का यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

इस समय भारत के बारे में बहुत ज्यादा आशावादिता का महौल है, जो न केवल गोष्ठियों में नजर आता है बल्कि विश्वभर में इसकी चर्चा है। इस आशावादिता को कायम रखने और इसके आधार पर सही फैसले लेने तथा अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने देश में बहुत कुछ करना होगा। जहां एक ओर सरकार की नीतियों का ध्यान घरेलू आर्थिक मुद्दों पर रहेगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं को विश्व की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करने और नये अवसरों की खोज करने पर ध्यान देते रहना होगा ताकि हम प्रभावी तरीके से अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। परिषद को अपने लिए स्पष्ट अनुसंधान एजेंडा तैयार करना होगा, जिससे कि सबसे पहले सभी परिषद की ओर देखें और उभरती विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के संबंधों को तय करने के लिए परिषद का पयाप्त मार्गनिर्देशन उपलब्ध हो।

बहुस्तरीय वार्ताओं के लिए, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में, विशेषज्ञता विकसित करने के अलावा परिषद को भारत के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय की अर्थव्यवस्थाओं को समझने के लिए आंतरिक विशेषज्ञता भी विकसित करनी होगी। दक्षिण एशिया में हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, उसे समझने के लिए हमें देश के अंदर और अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में चीन के बढते कदमों को देखते हुए हमें चीन की विकास प्रवृतियों और हमारे विकास पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को और गहराई से समझना होगा। परिषद को चीन के बारे में गहरी समझ विकसित करनी चाहिए, जो हमारे आर्थिक नियोजकों राजनयिकों और राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत मूल्यवान होगी। इस संदर्भ में चीन की गतिविधियों के बारे में अध्ययन के लिए परिषद जो कदम उठा रहा है, मैंने उसे पूरी दिलचस्पी के साथ सुना है और समझा है।

हमें पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, यूरोप और उत्तरी अमरीका की आर्थिक प्रवृतियों के बारे में भी विशिष्ट जानकारी की जरूरत है। एक मुद्दा, जो निकट भविष्य में उठ सकता है, वह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में भारत की सदस्यता का है। यह संगठन नये सदस्यो को आमंत्रित करेगा। हमें इसका सदस्य बनने की

लागत और लाभों का अध्ययन करना होगा। हमें समग्र एशियाई आर्थिक समुदाय या एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रभावों को समझना होगा। हम बहुत सारे मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने की योजना बना रहे हैं, हमें इसके प्रभावों का भी अध्ययन करना होगा। हमें भौगोलिक-राजनीतिक तंत्रों के प्रभावों की भी गहरी समझ प्राप्त करनी होगी जो नये आर्थिक संबंधों को जन्म दे रहे हैं। सीधी सादी बहु-स्तरीय व्यवस्था के मुकाबले इन समझौतों की लागत और लाभों की भी तुलना करनी होगी। यह परिषद अपनी गहरी समझ और विश्लेषण से सरकार के नीति निर्माताओं का मार्ग दर्शन कर सकती है ।

व्यापार का एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में कम अनुसंधान हुआ है और कम समझ है वह है सेवाओं में व्यापार, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं में व्यापार। विदेशी आर्थिक संबंधों के बारे में अधिकतर साहित्य और जानकारी माल व्यापार के बारे में होती है। लेकिन सेवाओं में व्यापार की स्थिति, विशेष रूप से श्रम सेवाओं में व्यापार की स्थिति बिल्कुल अलग है। व्यापार सेवाओं के क्षेत्र में अध्ययन अभी शुरू ही हुआ है और इसमें बहुत कुछ किया जाना है। विशेष रूपसे भारत में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। पिछले दशक में सेवाओं में व्यापार और विदेशों से आने वाले धन की मात्रा न सिर्फ माल व्यापार के मुकाबले ज्यादा रही है, बल्कि इससे हमारा भुगतान संतुलन भी काफी सुविधापूर्ण रहा है। इसलिए हम अपने बृहद आर्थिक प्रबंधन के लिए इसके महत्व को छोटा नहीं समझ सकते।

हमें यह समझना होगा कि जो सिद्धांत माल व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं वे कहां तक सेवाओं में व्यापार, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं में व्यापार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें अपनी कई सेवाओं की सापेक्ष क्षमताओं को अच्छी तरह समझना होगा जैसे मनोरंजन, व्यापार सेवाएं, खुदरा क्षेत्र, वित्त और बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं। हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में हम शामिल हों जिससे कि वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था में हमारे हितों को लाभ पहुंचे। इस पूरे जटिल क्षेत्र के बारे में हमारी समझ और बेहतर होनी चाहिए। विशेष रूप से रोजगार की दृष्टि से इसकी क्षमता और सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को देखते हुए ।

जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और विकास होता जा रहा है, उसे देखते हुए प्रतिभाओं के पलायन की दिशा पलटने की आशा रखनी चाहिए, विशेष रूप से प्रवासी भारतीय प्रतिभाओं के मामले में हमारी ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। मैं यह कहना चहूंगा कि पलायन की वापसी शुरू हो गई है। हम इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें अपनी घरेलू नीतियों में क्या परिवर्तन करने चाहिए, इस बदलती पलायन प्रवृति के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में क्या परिणाम हो सकते हैं? ये और अन्य प्रकार के प्रश्नों पर अनुसंधानकर्ताओं को ध्यान देना होगा ।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों का है। प्रति व्यक्ति आधार पर भारत के पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं है इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमें एक प्रमुख व्यापारी राष्ट्र बनना होगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा में व्यापार, पूरी तरह से वैसा नहीं है, जैसा औद्योगिक माल का होता है। यह बहुतही जटिल किस्म का है और भौगोलिक-राजनीतिक संबंधों पर बहुत निर्भर करता है। हमें प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने वाले पहलुओं का अध्ययन करना होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के इस व्यापार पर प्रभाव, विकासशील देशों में खनिजों और ऊर्जा के संसाधनों को हासिल करने के कुछ देशों के योजनाबद्ध अभियान और इन वस्तुओं के मुक्त बाजार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझना होगा तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश के

आर्थिक भविष्य की सुरक्षा के लिए नियोजकों और राजनयिकों को नीति संबंधी प्रस्तावों पर ध्यान देना होगा।

विदेशों से पूंजी प्राप्त करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने से वृहद-आर्थिक नीतियों के लिए, विशेष रूप से वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के लिए नये मुद्दे सामने आए हैं और हमें आंतरिक और विदेशी पूंजी निवेश के बीच संतुलन रखना होगा। विदेशों से आने वाली पूंजी की सुरक्षित सीमाओं के बारे में हमें अपनी समझ को बेहतर बनाना होगा। विनिमय दर के प्रबंधन के सबंध में भी कई नये मुद्दे उठते हैं। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के सबंध में हमें गहरे विश्लेषण की आवश्यकता है।

स्पर्धाशीलता के क्षेत्र में विश्लेषण का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद का परम्परागत अनुसंधान क्षेत्र रहा है। जैसे-जैसे विश्व स्तर पर आर्थिक अंतर-संबंध तेजी से बदल रहे हैं, हमें विभिन्न क्षेत्रों में स्पर्धाशीलता के बारे में अपनी समझ बढ़ानी होगी, जिनमें औद्योगिक संगठन, औद्योगिक उन्नति तथा और अधिक एकीकृत विश्व के लिए आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं के बारे में अपनी समझ को बेहतर करना होगा। इसी के साथ ही प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन, विपणन, आर्थिक साधनों की उपलब्धता और सर्विस डिलीवरी के तौर तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं, जिसका भारतीय फर्मों के विकास पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इस बारे में भी गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि किसी भी चिंतनशील संस्था को देश के अंदर और विदेश में जनमत पर ध्यान देना चाहिए और हमारे देश के हित से जुड़े मुद्दों पर विचारों को प्रभावित करना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मताधिकार की पुर्नव्यवस्था के लाभों और हानियों के बारे में देश के अंदर पर्याप्त गहराई से कोई चर्चा नजर नहीं आई है। न ही एशियाई मुद्रा यूनियन के बारे में कोई चर्चा दिखाई देती है, जिसके बारे में कुछ क्षेत्रों में विचार विमर्श चल रहा है और न ही इस बारे में कोई चर्चा है कि नई उभरती विश्व व्यवस्था में भारत का स्थान क्या होगा।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद जैसी चिंतनशील संस्थाओं को विश्व में भारत के स्थान और बढ़ती वैश्विक अंर्तनिर्भरता के परिणामों पर सार्वजनिक बहस में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। मुझे कई बार यह देखकर निराशा होती है कि हमारे देश में, विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं में, विश्व के साथ और विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों के बदलते स्वरूप को ठीक तरह से समझा नहीं जा रहा है। अकसर ही हम ऐसा राजनीतिक रवैया दिखाते हैं, जो पुराने समय, बल्कि बहुत पुराने समय जैसा लगता है और तेजी से होते वैश्वीकरण तथा विश्व की एकीकृत व्यवस्था में हमारे आज के हितों के अनुरूप नहीं होता। मैं समझता हूं कि भारत को ज्यादा से ज्यादा विश्व व्यवस्था की साथ जुड़ना है और आसपास के क्षेत्र के साथ और ज्यादा एकरूप होना है। आज भी हमारी ऊर्जा सुरक्षा बहुत हद तक दुनिया के कई देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों पर निर्भर है। हमारी खाद्यान्न सुरक्षा, हमारी प्रौद्योगिकी सुरक्षा, यहां तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का दुनिया में हो रही घटनाओं से गहरा संबंध है।

फिर भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि भारत और विश्व के बीच बढ़ती अंर्तनिर्भरता के बारे में और हमारी घरेलू नीतियों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में देश के अंदर बहुत कम समझ है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद जैसी

चिंतनशील संस्थाओं को इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने तथा जनमत को विकसित करने और नीति निर्धारण में योगदान देना होगा।

परिषद अब अगले 25 वर्षों के लिए अपने आपको तैयार कर रही है। यही चुनौती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में भारतीय अनुसंधान परिषद को स्वीकार करना होगा मैं एक बार फिर उन सभी को मुबारकबाद देता हूं जो परिषद की उन्नति और विकास के साथ जुड़े रहे हैं। इन 25 वर्षों में आपने पूरी विशिष्टता के साथ् देश की सेवा की है, लेकिन मैं समझता हूं कि श्रेष्ठ कार्य अभी होना है। इन शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं कि देश की जनता की सेवा के लिए आप आने वाले अनेक वर्षों तक उपयोगी और रचनात्मक अनुसंधान करते रहें।

******